पूंजीवाद

ये पूंजीवाद है दोस्तो,
ये मुनाफ़े की व्यवस्था है,
महंगा है पानी यहां लहू आदमी का सस्ता है।
खून बहता है सड़कों पर
पानी दुकानों पे बिकता है,
हर नुक्कड़ पे मिल जायेंगे ठेके शराब के,
एक नल पानी का कहीं दिखता है।
ये पूंजीवाद है दोस्तो....
बिकती है बच्चे की मुस्कान,
मां का प्यार यहां बिकता है,
मैंने देखा है राखी के धागों में,
बहन का प्यार यहां बिकता है।
ये पूंजीवाद है दोस्तो...
मज़दूर बिकता है रोज कारखानो में,
खेतों में किसान यहां बिकता है,
देश की सरहदों पर खड़ा है जो प्रहरी बनकर,
हर वो जवान यहां बिकता है।
ये पूंजीवाद है दोस्तो...
हुस्न बिकता है, जिस्म बिकता है,
बिकता यहां हर माल है,
ये दुनिया एक बाजार है दोस्तो,
हम सब इसी बाजार का ही तो माल है।
ये पूंजीवाद है दोस्तो...
नेता बिकता है, संसद बिकती है,
न्याय को बिकते हुए देखा है,
ईमान बिकता है आत्मा बिकती है,
इंसान को बिकते हुए देखा है।
ये पूंजीवाद है दोस्तो,
ये मुनाफ़े की व्यवस्था है,
महंगा है पानी यहां,
लहू आदमी का सस्ता है।

-भारत सिंह

कहते कुछ होता कुछ

कहते कुछ होता कुछ
बेटी बचाओ अभियान चला पर बंद न होती एम.टी.पी.
बढते जाते विकास के चर्चे घटती जाती जी.डी.पी.
चुनावी वादे महज थे जुमले जीत के कहती बी.जे.पी.
पापी, मुजरिम बनें हैं लीडर अब कहलाते वी.आई.पी.
सच्ची-झूठी न्यूज बनाओ लक्ष्य है अपना टी.आर.पी.
ट्रेन लुटे या जहरखुरानी मस्त है सारी जी.आर.पी.
पाक बना आतंक का अड्डा मानो पी.एम.एल.पीपीपी
(एम.टी.पी.-मेडिकल अर्मिनेशन्स ऑफ़ प्रेग्नेंसी/गर्भपात
जी.डी.पी.-ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट
टी.आर.पी.-टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट
जी.आर.पी.-गवर्नमेंट रेलवे पुलिस
पी.एम.एल.,पीपीपी-पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी)

मरियम उस्मानी वाया ईमेल

लोमहर्षक सुनपेड़ अग्निकांड पर कोई सच नहीं बोलना चाहता!

पेज एक का शेष

अभी कुछ समय पहले जमानत हो गयी थी और जितेन्द्र के पिता की जेल में ही मृत्यु हो गयी थी। हत्या का यह मुकदमा अब पूरा हाने को है जिसमें सभी 10 आरोपियों का दोषी पाया जाना तय समझा जा रहा है। जितेन्द्र ने शुरू में तो पुलिस से मिल कर राजपूतों पर क्रॉस केस बनवाने का प्रयास किया था और विफ़ल होने पर राज़ीनामे के लिये काफ़ी हाथ पांव मारे लेकिन बात बनी नहीं। अब करने या मरने का उसके पास यही आखरी मौका था।

केस का एक दूसरा पहलू पति-पत्नी के आपसी तनावपूर्ण सम्बन्धों का भी गौरतलब है। जांच पड़ताल में यह बात काफ़ी उभर कर सामने आ रही है। इनके आपसी सम्बन्ध भी काफ़ी तनावग्रस्त रहते थे और रेखा अक्सर अपने मायके या अपनी बहन-बहनोई के पास डबुआ कॉलोनी में फ़रीदाबाद रहती थी। इस बात को लेकर भी दोनों पति-पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे।

मौका ए वारदात से पुलिस को कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे खिड़की द्वारा पेट्रोल फ़ेंके जाने व तिल्ली फ़ेंकना सिद्ध होता हो। यह भी लगभग सिद्ध हो चुका है कि आग पेट्रोल से नहीं केरोसीन से लगाई गयी थी और बिस्तर जिस वृत्ताकार ढंग से जला है उससे पता चलता है कि तेल भीतर से ही गिराया गया है। अब सुलझाने वाली बात केवल इतनी रह गयी है कि यह काम पति ने किया अथवा पत्नी ने या दोनों ने।

जो कुछ भी हुआ वह एक आपराधिक घटना थी जिसका निवारण विधिवत तयशुदा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाना चाहिये था। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी को खोज कर उचित कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये थी। परंतु ऐसा कुछ न करके, फ़ौरन ही वारदात को दलित बनाम दबंग का नाम देकर एक जातीय मसला खड़ा कर दिया गया। पूरी हरियाणा सरकार हिल गयी और बचाव मुद्रा में पसर गयी। दलितों को राजनीति का मोहरा बनाने वाली सरकार के स्थानीय नेताओं तथा अफ़सरों के अलावा चंडीगढ तक से अफ़सर दौड़ते हुए पहुंचे। मानो यह सब काफ़ी नहीं था, मुख्यमंत्री खट्टर भी 10 लाख का चैक लेकर आ पहुंचे। जितेन्द्र को चैक तो दिया सो दिया सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दे दिया। जाहिर है खट्टर सरकार यह सब उन विपक्षी नेताओं से होड़ में पिछड़ने के डर से कर रही थी जो भी वारदात पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे।

ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी था कि एक वर्ष पूर्व जितेन्द्र के परिजनों द्वारा कत्ल किये गये राजपूतों के लिये कोई रोने के लिये क्यों नहीं आया? उनके द्वारा पटे पर लिये गये खेतों की खड़ी फ़सल बर्बाद हो गयी। उनके परिवार दाने-दाने को मोहताज हो गये। तब कहां चली गयी थीं ये ड्रामेबाज़ी? ये 'संवेदनायें'? क्या यह समाज को जातीय आधार पर बांटने व लड़ाने का कुत्सित राजनीतिक प्रयास नहीं है? सरकार ने इस गांव में जो जातीय बवंडर खड़ा कर दिया है क्या वह यहां के निवासियों में कभी भाईचारा पनपने देगा? विदित है कि इस गांव का आपसी भाईचारा बेमिसाल माना जाता था।

7 निर्दोष पुलिसकर्मी निलम्बित

जितेन्द्र परिवार द्वारा मांगी गयी सुरक्षा के नाम पर वहां 7 पुलिसकर्मी तैनात किये गये थे। वे सातों पुलिसकर्मी होने से पूर्व इन्सान हैं, कोई रोबोट नहीं। वे छुट्टी भी जायेंगे, आराम भी करेंगे, नित्यकर्म भी करेंगे। मौके पर मौजूद 3 पुलिसकर्मी जितेन्द्र के घर के निकट हो रहे कीर्तन की भी निगरानी कर रहे थे जहां आधे से ज़्यादा गांव एकत्रित था। आगजनी की घटना होते ही 3-4 मिनट में वे तीनों पुलिसकर्मी मौका ए वारदात पर पहुंच गये। उन्होंने पाया कि जितेन्द्र के घर की कुंडी अन्दर से बन्द थी। जितेन्द्र द्वारा कुंडी खोलने के बाद ही वे भीतर प्रवेश कर पाये और तुरंत सभी को बल्लबगढ के असपताल पहुंचाने के साथ-साथ उन्होंने अपने अफ़सरों को भी सूचित कर दिया।

इस सब के बावजूद वारदात के लिये इन्हें ही दोषी ठहरा कर तुरंत निलम्बित कर दिया गया। राजनीतिक आकाओं को स्वयं को पाक-साफ़ जो दिखाना था। पुलिस वाले बाहरी हमलावर से ही तो किसी की रक्षा कर सकते हैं, भीतर ही भीतर कोई वारदात करे तो पुलिसकर्मी क्या कर सकते थे? उनकी ड्यूटी जितेन्द्र के बिस्तरों में सोने की तो लगाई नहीं गयी थी।

इस बीच अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग कूद-कूद कर ज़िले के अफ़सरों पर पड़ रहा है। उसका कहना है कि जब उसने खुद डसीपी बल्लबगढ व सीपी को इस परिवार की सुरक्षा बढाने को कहा था तो फ़िर कैसे यह वारदात हो गयी? ऐसे में लगे हाथ यह भी जोड़ दिया गया कि जब जितेन्द्र की पत्नी ने (घटना से पूर्व) सुरक्षा की गुहार लगाई थी तो अफ़सरों ने जवाब दिया था कि कोई मरा तो नहीं।

विर्ग के बतौर एक एकजुट होना होगा

जब से देश में संघी सरकार काबिज हुई है तब से मानों कट्टर हिन्दूत्ववादी नेताओं का दिमाग सातवें आसमान पर चढ गया है। और वे एक से बढकर एक फ़रमान ज़ारी कर देश के अंदर साम्प्रदायिक माहौल खड़ा कर रहे हैं। यही कारण है कि विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया एक लेख में मुस्लिम विरोधी बातें करते हुए मुसलमानों से दो बच्चे से अधिक पैदा नहीं करने का फ़रमान जारी करते हैं। मुसलमानों पर मुकदमा चलाने की नसीहत दे डालते हैं तथा साथ ही साथ मुसलमानों को सभी तरह की सुख सुविधा मतलब, राशन कार्ड, नौकरी, शैक्षिक डिग्री तथा सरकार की तरफ़ से मिलने वाली हर तरह की सुविधाओं से वंचित करने का फ़रमान सुना देते हैं और मुसलमानों की बढती संख्या को हिन्दुओं के लिये खतरे की घंटी बताते हैं। अब सवाल है कि जिस देश के अंदर मुस्लिमों की संख्या 15-16 प्रतिशत हो और जिसे पहले ही दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया हो, जिसे अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया हो, जहां देशभक्ति साबित करने के लिये हर रोज़ नया पैमाना बनाया जाता हो उस समुदाय के बारे में ऐसा बयान तोगड़िया की मध्ययुगीन सोच को उज़ागर करता है। आज तथाकथित जनवाद का भी गला घोंट कर देश के अंदर नाजीवादी (फ़ासीवादी) राज्य कायम करने की आहट को स्पष्ट समझा जा सकता है।

अब सोचने की बात है कि क्या हमारा जो जीवन स्तर लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। क्या इसके लिये मुसलमानों को दो से अधिक बच्चा पैदा करना जिम्मेदार है? हम मज़दूरों से जो 5000 रुपये, 6000 रुपये में 12, 14 घंटा काम करवाने का छूट, किसानों से जबरन जमीन छीनने के लिए छूट, महिलाओं को 3500 रुपये-4000 रुपये में काम करवाने तथा रात में भी महिलाओं से काम करवाने की छूट, 14 साल के बच्चे से काम करवाने का छूट, मालिक को रजिस्टर रखने व रिटर्न भरने से छूट, जब जी करे रखो जब जी करे निकालो, श्रम कानून को खत्म करके पूंजीपतियों को लूटने की खुली छूट, मज़दूर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ़ जब आवाज़ उठाये तो उसका बर्बर दमन, इन सबके लिये कोई मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है देश के पूंजीवादी व्यवस्था जिसकी नुमांइदगी आज संघी सरकार कर रही है। मोदी, तोगडिया सिंघल जैसे लोग जो डरते हैं इस देश के मज़दूर से, किसान से, छात्र नौजवान से और इसलिये ये लोग लगातार धार्मिक उन्माद फ़ैलाकर हमें आपस में बांटकर, इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था को संरक्षण प्राप्त करवाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि तोगडिया और संघी सरकार के धार्मिक उन्माद का भण्डाफोड किया जाय और जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की दीवार को तोड़ते हुए एक वर्ग के बतौर इकट्ठा होकर पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर समाजवादी व्यवस्था, समाजवाद (मज़दूर राज्य) के लिए संघर्ष को तेज़ किया जाये।

-एक मज़दूर फ़रीदाबाद

अब सोचने की बात है कि क्या हमारा जो जीवन स्तर लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। क्या इसके लिये मुसलमानों को दो से अधिक बच्चा पैदा करना जिम्मेदार है? हम मज़दूरों से जो 5000 रुपये, 6000 रुपये में 12, 14 घंटा काम करवाने का छूट, किसानों से जबरन जमीन छीनने के लिए छूट, महिलाओं को 3500 रुपये-4000 रुपये में काम करवाने तथा रात में भी महिलाओं से काम करवाने की छूट, 14 साल के बच्चे से काम करवाने का छूट, मालिक को रजिस्टर रखने व रिटर्न भरने से छूट, जब जी करे रखो जब जी करे निकालो, श्रम कानून को खत्म करके पूंजीपतियों को लूटने की खुली छूट, मज़दूर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ़ जब आवाज़ उठाये तो उसका बर्बर दमन, इन सबके लिये कोई मुसलमान जिम्मेदार नहीं है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब